[illegible] [illegible] 2025

[illegible]

300 Marks

कौटिल्य एकेडमी

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
Main Answer Sheet

124 1/2 / 300

[illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है जिस [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होती है

(3)

B आयुष अर्थात आयुर्वेद, योग आदि संबंधित जीवन प्रक्रिया, जिसे वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली के तहत अपनाया जाना चाहिए।

2014

यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी

(1)

C जन्म एवं मृत्यु संबंधित आंकड़ों का अध्ययन एवं जनगणना प्रणाली जन्म मृत्यु समंक कहलाती है यह जनगणना रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित व तैयार किया जाता है

(2)

D किसी व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय या अनुचित काम करना ही भ्रष्टाचार है विश्व में ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल भ्रष्टाचार रोकने हेतु वैश्विक संस्था है

धारा व आधिनियम बताते

(1.5)

E अखिल भारतीय शैक्षिक तकनीकी परिषद भारत में तकनीकि विकास व प्रशिक्षण हेतु शीर्ष संस्था है। गठन - योजना आयोग की सिफारिश पर हुआ था।

1945, दिल्ली

(1.5)

एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है, जो मुर्गियों, [illegible] के माध्यम से संचारित होती है। लक्षण - सर्दी जुकाम, तेज बुखार फेफड़ों में संक्रमण आदि।

H_5N_1

(1.5)

Head Office: Rajwada Chowk, Indore : 0731-4033333, [illegible]

प्रश्न संख्या

G. यूनेस्को [illegible] ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक [illegible] संरक्षण हेतु स्थापित किया है। भारत में यूनेस्को द्वारा [illegible] सूची में [illegible] को सूचीबद्ध किया गया है।

10

तथ्य लिखें

H. [illegible] विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो स्वास्थ्य [illegible] 1948 में, [illegible] सुरक्षा के लिए महामारी नियंत्रण हेतु नियमावली तैयार करता है। भारत में संगठन द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया।

मुख्यालय जेनेवा

1

तथ्य लिखें

I

J. शरीर के अंदर मौजूद एण्टीबॉडी द्वारा प्रतिजन से लड़ना ही सक्रिय प्रतिरक्षण है।

1

तथ्य लिखें

K. किसी भी व्यवसाय में उत्पाद की क्रय एवं उपभोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। इसके संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित

2019

½

L

(1) यह भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा व देखभाल हेतु उच्चतम संस्थान हैं जो भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। वर्तमान में लगभग (6) एम्स कार्यरत हैं। जैसे - भोपाल, एम्स।

×

1.5

[illegible] की [illegible] मुख्य [illegible]
[illegible] गरिमापूर्ण जीवन को
[illegible] महिलाओं को सुरक्षा [illegible] संविधान में कई प्रावधान किए
सम्मानजनक जीवन हेतु
गए हैं जो निम्न हैं:

1) अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समानता का अधिकार
2) अनु. 15 - धर्म, लिंग, जाति, जन्म आदि आधार पर भेदभाव निषेध एवं 15(क) राज्य द्वारा संरक्षण हेतु उचित प्रयास
3) नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनु. 39 - समान कार्य हेतु समान वेतन एवं 39(क) कार्य अनुसार न्याय संगत एवं प्रसूति सहायता उपबंध
4) अनु. 47 - उचित पोषाहार एवं पोषण हेतु प्रयास।

आदि तमाम प्रयासों के अलावा कई नोविधिक प्रयास भी शामिल हैं
यह अधिनियम मूलतः 1989 को अधिनियमित किए जाने के साथ ही प्रभाव में आया है जिसने देश के तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति सुरक्षा एवं सम्मानपूर्वक जीवन में योगदान दिया है परन्तु इसकी असफलता हेतु कई कारक जिम्मेदार हैं:

1) कई झूठे एवं निराधार आरोपों का सामने आना। जि[illegible] अधिनियम की गंभीरता को ही नकार दिया।
2) लोक अधिकारियों एवं प्रशासन के ढीले रवैये से अनुसार सूचना व रिपोर्ट दर्ज न होना।
3) जाति, जनजाति के लोगों के प्रति आरोपी [illegible] माहौल बनाना व इस हेतु कोई नियम न होना।

निष्कर्षतः प्रशासनिक स्तर पर कठोरता [illegible]

[illegible] असंगठित क्षेत्र [illegible] मजदूर कार्यरत हैं [illegible] असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का [illegible] में [illegible] सरकार द्वारा [illegible] आधार पर कई [illegible] किए जाते हैं :

1) पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना : 2015 से शुरू हुई योजना के तहत यूआईडी, श्रमिक कार्ड एवं स्वास्थ्य बीमा संबंधी आदि प्रावधान शामिल है।

2) मुख्यमंत्री उद्योग योजना – म.प्र. सरकार की अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों हेतु नया उद्योग शुरू करने हेतु ऋण सुविधा।

3) मुद्रा योजना, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

निष्कर्षतः मजदूरों के कल्याण हेतु भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों का अनुसरण किया जाता है।

D) मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु दर प्रति 1000 माताओं में 173 है जबकि भारत में यह आंकड़ा 130 के लगभग है। इस दर को कम करने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं :

1) जननी सुरक्षा योजना – 2005 में शुरू एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु माता एवं अन्य कार्यकर्ता को वित्तीय लाभ।

2) जननी शिशु सुरक्षा योजना – 2011 में शुरू, गर्भवती महिला हेतु निःशुल्क परिवहन, जाँच, पोषण आहार सुविधा।

3) मंगल दिवस योजना – 2007-08 में शुरू, गर्भावस्था के दौरान हेतु प्रत्येक मंगलवार स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करना।

4) संजीवनी 108 – निःशुल्क एंबुलेंस सुविधा ताकि मातृत्व शिशु सुरक्षा सुनिश्चित।

निष्कर्षतः तमाम प्रयास मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ना केवल वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण निर्देशन [illegible] है। संगठन की भूमिका पोलियो उन्मूलन, चेचक उन्मूलन संदर्भ में बखूबी समझी गई है परन्तु अन्य रोगों व स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यप्रणाली अपेक्षित कार्यों के अनुरूप नही है। इसी संदर्भ में अमेरिका संगठन से बाहर आ गया है। संगठन में कई अल्पविकसित विकासशील देशों के अनुसार कदम उठाये जाते है जैसे हाल ही में चीन [illegible] के कारण कोरोना वायरस से लड़ने की भूमिका को कमजोर देखा गया। संगठन में कार्यप्रणाली बिना किसी दबाव के तीव्र व लक्षित होनी चाहिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कसौटी पर नही ठहर रहा है व इसमें सुधार की गुंजाइश है।

4 निरोधात्मक कार्यक्रम से तात्पर्य, ऐसे कार्यक्रम जो रोगो से बचने हेतु पूर्व में ही अपनाए जाते है जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। कुछ प्रमुख निरोधात्मक कार्यक्रम निम्न है:

1) सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम - 1985 में शुरू राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा। सात प्रकार के टीकों माध्यम से प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत करना है।

2) मिशन इन्द्रधनुष - 2015 में शुरू बच्चों, गर्भवती मा[illegible] की टीकाकरण के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा।

3) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - इसके तहत ग्रामीण एवं श[illegible] स्वास्थ्य मिशन शामिल है।

3) राष्ट्रीय पोषण मिशन - कुपोषण आदि से बचाव

किशोरी की व्यक्ति में असंतुलित पोषक आहार की कमी या आधिक्य होना जो उसकी शारीरिक, मानसिक क्षमता को अवरुद्ध करे, कुपोषण कहलाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

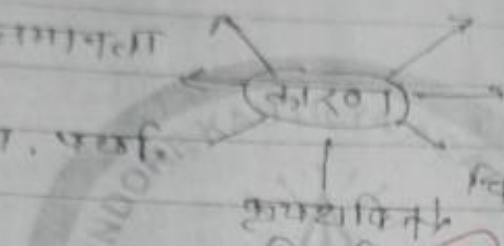

(1) कम उम्र में विवाह (2) गर्भावस्था में कुपोषण
(3) शिक्षा, जागरूकता का अभाव (4) पारिवारिक पोषण स्तर की कमी
लैंगिक असमानता

कारण → देश में खाद्य संकट, अनुपलब्धता
(5) आर्थिक, पर्या. कारण
विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ
सामाजिक निर्धनता

बचाव हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, बाल संजीवनी मिशन, समन्वित बाल विकास योजना आदि कार्यक्रम संचालित।

कोविड-19 रोग कोरोना वायरस से संक्रमित एक भयावह संक्रामक रोग है जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई मानी जाती है। इसके प्रसार के कारण निम्न हैं:

1) छींकने, खाँसने के कारण
2) परस्पर संपर्क में रहने के कारण
3) जल, वायु संपर्क से
4) अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन के कारण यह भारत में भी प्रसारित हुआ।

L महिला स्वास्थ्य ही देश का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित
सकता है। इस दिशा में केन्द्र व मध्यप्रदेश सरकार
कई कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं :

1) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : वायु प्रदूषण से बचाव
स्वच्छ गैस उपयोग हेतु निःशुल्क गैस सिलेण्डर प्रदान

2) जननी सुरक्षा योजना : 2005 में शुरू हुई योजना
सुरक्षित व संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु।

3) प्रोजेक्ट मुस्कान – महिलाओं में एनीमिया रोकने

4) समन्वित बाल विकास योजना – 1976 में शुरू
के पोषण स्तर में वृद्धि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु

4) किशोरी पोषण योजना आदि।

3

किसी भी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी एवं अधिकता के संदर्भ में शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही कुपोषण कहलाती है। यह सामान्यतः बच्चों एवं महिलाओं से जुड़ी गंभीर समस्या है। वर्तमान में लगभग 19.3 (आबादी) कुपोषण से ग्रसित है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत उन 88 देशों में शामिल है जो 2025-30 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है।

मध्यप्रदेश भारत का एक सर्वाधिक कुपोषित राज्य है इसी के साथ भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 101 वे. स्थान में समायोजित है। कुपोषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1) कम उम्र में विवाह होने से शरीर परिपक्व न हो पाना।
2) लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं में भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की कमी देखी जाती है।
3) क्रयशक्ति में कमी एवं निर्धनता।
4) पौष्टिक गुणवत्तायुक्त आहार एवं इसके प्रति जागरूकता की कमी।
5) पारिवारिक खाद्य सुरक्षा की कमी एवं अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां।
6) अस्वच्छ वातावरण जिसमें स्वच्छ पेयजल अनुपलब्ध एवं गंदगी के तहत शारीरिक विकास की कमी।

[illegible] कुपोषण [illegible] परिणामस्वरूप [illegible] समस्याएं हो रही हैं। इन परिणामों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

1) भारत की जीडीपी में कुपोषण के प्रभाव से लगभग 2% से 3% प्रतिशत का नुकसान होता है।

2) बच्चों एवं बालिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है परिणामस्वरूप बाल रोग से ग्रसित हो जाते हैं।

3) स्त्रियों में रक्ताल्पता, घेंघा रोग एवं बच्चों में मरास्मस, क्वाशियोरकर जैसे रोग।

4) मानसिक मंदता से देश का मानव संसाधन प्रभावित होता है।

इन परिणामों के मद्देनजर ही सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कुपोषण से बचाव व निदान हेतु कई कार्यक्रम संचालित हैं -

- बाल संजीवनी मिशन
- राष्ट्रीय पोषण मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 2013
- मंगल दिवस योजना
- सांसद चूल्हा कार्यक्रम
- विशेष पोषण आहार कार्यक्रम
- समन्वित बाल विकास योजना

निष्कर्ष: इन तमाम प्रयासों के साथ.
आशा करती हूँ कि, सम्भवतः कार्य करती की इस समस्या
के निदान में एक अहम होगा है।

7

भारत में प्रवासी श्रमिक, मूलतः [illegible]
राज्यों से आर्थिक पिछड़ापन से मौजूद है जो मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्यों से प्रवास करते हैं। इन श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक जीवन अधिकार है एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी निम्नतम स्थिति तहत देखा जाता है।

इसी दृष्टि से इन श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं:

1) संगठित रोजगार का अभाव।

2) स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं।

3) कार्य के घंटे एवं इस आधार पर उचित [illegible] में असमानता एवं अस्थायित्व।

4) आवास की समस्या एवं पारिवारिक [illegible]

5) बच्चों के शैक्षिक भविष्य की समस्या

6) सामाजिक सुरक्षा का अभाव

7)

3

[illegible]

[illegible] मृत्यु दर [illegible] 48 है। [illegible] में [illegible] को शामिल करने एवं महिला बाल विकास हेतु कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

1) जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू हुई योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इस हेतु संस्थागत प्रसव करवाने पर माता एवं प्रेरित करने वाले कार्यकर्ता को वित्तीय अनुदान दिया जाता है।

2) जननी शिशु सुरक्षा योजना - 2011 में शुरू हुई योजना के तहत मध्यप्रदेश में निःशुल्क परिवहन जाँच, पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था गर्भवती महिला एवं बच्चे के तहत की जाएगी।

3) विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना - बीपीएल महिला हेतु - गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता।

4) विशेष पोषण कार्यक्रम

5) पूरक पोषण कार्यक्रम एवं संयुक्त पोषण कार्यक्रम

6) बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम — 1995 में शुरू इस कार्यक्रम शालाओं में उपस्थिति तथा के माध्यम से बालिकाओं के पोषण स्तर को सुनिश्चित करता है।

8) सबला योजना — इसके तहत किशोरी बालिकाओं (11-14 वर्ष) एवं (14-18 वर्ष) के उत्तम स्वास्थ्य हेतु सरकार द्वारा उचित पोषण की व्यवस्था की जाएगी।

5

[illegible]

(1.5) 2014 से ... 2019 - ...

बच्चों में हृदयरोग से बचाव हेतु किया जाने वाला
... को ... प्रथम व द्वितीय सप्ताह में
किया जाता है। ... माह मनाते (1)

अपनी शारीरिक, मानसिक अक्षमता के कारण प्रत्येक
स्वस्थ नहीं व्यक्ति निःशक्त कहलाते हैं। इन हेतु
सुगम्य भारत योजना क्रियान्वयन किया गया। (2)

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बालकों बालिकाओं
के स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षिक भविष्य हेतु नीति व
कदम उठाये जा रहे हैं। (1)
2014

किसी वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्ति एवं व्यय के मह
के अन्तर को राजकोषीय घाटा कहते हैं जिसमें
सब्सिडी शामिल नहीं होती है।

... दूरसंचार - अनौपचारिक कार्य - ... हेतु ऋण एवं व्यापार के ... मार्ग प्रशस्त करना ... उपलब्ध कराना।

(2.5)

M वायु, जल, और आदि संपर्कों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोग। उदा.- हैजा, मलेरिया, कोविड-19, एड्स, पीलिया, टायफाइड आदि

(2)

N शरीर में आयरन की कमी से रक्तअल्पता अर्थात् एनीमिया का रोग होता है। बचाव- फोलिक एसिड गोलियां
कार्यक्रम- मध्यप्रदेश सरकार का लालिमा अभियान।

(2.5)

O एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सभी सुविधाएं शामिल है।

(1.5)

K मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण एवं इसके घटकों का प्रभावित होना ही प्रदूषण है जैसे - वायु, मृदा, प्रदूषण आदि।

(1.5)

L जनता की समस्याओं एवं कार्यों के क्रियान्वयन ... स्थापित केन्द्र जो समय अनुरूप कार्य संचालित कर... मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ... किया गया।

(1)

ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता एवं मात्रा से समझौता किए बिना तकनीकी शैक्षिक व्यवस्था प्रदान की जाए। इसमें कुल, योग्यता, वर्ग की भागीदारी निहित है।

1.5

एक भारत का उच्च तकनीकी शैक्षिक संस्थान है जो जेईई एवं गेट परीक्षा के माध्यम से संस्थान मे प्रवेश करवाता है। वर्तमान में लगभग (16) आईआईटी संस्थान संचालित है।

23 IITs (1.5)

1961

1.5

ऐसी मानव शक्ति जो शारीरिक मानसिक तौर पर दक्ष हो एवं देश कि आर्थिक विकास को सुनिश्चित करे। ऐसी मानव पूंजी ही दक्ष मानव शक्ति है।

2

[illegible]

- कुशल मानव संसाधन का निर्माण एवं विकास
- देश के आर्थिक संवृद्धि में सहायक
- रोजगार एवं प्रगति के एक सूचकांक के रूप में सहायक
-

2

उत्तर क्रमांक

2 B व्यवसायिक शिक्षा से तात्पर्य - व्यवसाय, रोजगारोन्मु
शिक्षा से है। भारत में व्यवसायिक शिक्षा की महत्ता
अन्य देशों की तुलना में कम आंकी जाती रही है जि
परिणामस्वरूप ही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में
हुई है। इसकी महत्ता के चलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नी
2020 में पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन स्तर पर छठी के
व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है।

भारत में आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थाने
माध्यम से व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं कुशल
ता है। व्यवसायिक शिक्षा भारत में रोजगार
में निर्भरता को कम
पूर्ति तकनीकि शिक्षा

3

[illegible]

[illegible] कार्य पूरे किए जा सकते हैं।

[illegible]

- कई शैक्षणिक कार्य [illegible] किए जाए।

- स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से निरन्तर अध्यापन जारी रखा जा सकता है।

- कई ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसे यूट्यूब या कोई एप परीक्षा संबंधी अध्ययन पूर्ण करने में कारगर साबित हो रहे हैं।

(3)

अतः ई-रक्षा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

प्रशासनिक सेवा कार्यपालिका का अहम अंग है जिसे अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय स्तर पर तीन प्रकार की सेवाओं में प्राथमिक सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा है। जिसकी विशेषताएं निम्न हैः

1) चयन यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित कर एवं 2 वर्षीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण।

2) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एवं केन्द्र एवं राज्य दोनों में सेवाएं देते हैं।

3) इनपर मुख्य नियंत्रण केन्द्र सरकार का होता है इससे संबंधित समस्या निवारण हेतु प्रशासनिक अधिकरण का गठन।

निष्कर्षतः कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है।

Head Office : Rajwada Chowk, Indore : 0731-4083933, 9111100825

सार्क अर्थात् दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
स्थापना - 1985 में, मुख्यालय - काठमांडू ; संगठन
8 सदस्य (भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान
बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका)
उद्देश्य : सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार सं
↳ दक्षिण एशियाई क्षेत्र विकास सुनिश्चित।
भविष्य : वस्तुतः स्थापना विकासोन्मुखी उद्देश्य
सदस्य देशों के निजी हित टकराव एवं साम्राज्
तुष्टीकरण नीति से संगठन की महत्ता पर चोट
समय अनुसार सम्मेलन न होना व उद्देश्यों
से सार्क की महत्ता पर प्रश्न उठते हैं। इस दिश
को एकजुट होकर संगठन के मूल भाव पर ध्

[illegible] बाद न लिखें

सार्क अर्थात् दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की
स्थापना 1985 में, मुख्यालय - काठमांडू; संगठन - कुल
8 सदस्य (भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल,
बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका)

उद्देश्य: सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार संचालन
दक्षिण एशियाई क्षेत्र विकास सुनिश्चित।

भविष्य: वस्तुतः स्थापना विकासोन्मुखी उद्देश्य से हुई है परन्तु
सदस्य देशों के निजी हित एकपक्ष एवं साम्राज्यवादी मंशा,
ध्रुवीकरण नीति से संगठन की महत्ता पर चोट पहुँचती है।
य अनुसार सम्मेलन न होना व उद्देश्यों के प्रति कार्य
सार्क की महत्ता पर प्रश्न उठते हैं। इस दिशा में सदस्य
एकजुट होकर संगठन के मूल भाव पर ध्यान दिया जा

Head Office : Rajwada Chowk, Indore : 0731-4083933, 9111100925

[illegible] निर्धारित किया जाता है।
आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख (5) स्तंभ हैं —
1) अर्थव्यवस्था 4) जनसांख्यिकी
2) अवसंरचना 5) माँग
3) प्रौद्योगिकी

सरकार द्वारा महामारी के दौर में आत्मनिर्भर भा[रत] को सहयोग देने हेतु पैकेज की भी घोषणा की है

निष्कर्षतः इस अभियान से वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं अपितु दुनिया की मदद ही की जाएगी।

J भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारत में कृषि संबंधी तकनीकि अनुसंधान, अनुप्रयोगों हेतु शीर्ष निकाय है। इसके योगदान की श्रृंखला निम्न है —
1) विभिन्न वाणिज्यिक फसलों पर अनुसंधान [illegible] उसके पोषणात्मक स्तर की जाँच जैसे - बीटी का[illegible]
2) नवीन सिंचाई प्रणालियों पर शोध
3) मृदा स्वास्थ्य परीक्षण व इस दिशा में जा[illegible]

निश्चित ही परिषद कृषि [illegible] उत्पादन प्रक्रिया में अहम योगदान देती [illegible]

[illegible]

... लैंगिक ... [illegible]

... अनुसार ... [illegible]

... [illegible]

... लिंगानुपात ... [illegible]

बाल विवाह के स्तर ... [illegible] ... जाता है ... [illegible]

मृत्यु दर के संदर्भ में ... [illegible]

... की गई है। ... [illegible]

हाल ही में सर्वे के ... अपने ... [illegible]

पारिवारिक स्वास्थ्य ... देश ... विकास का ... [illegible]

किया जाता है।

(3)

जन्म मृत्यु संबंधी मूलतः जनगणना आधारित आंकड़े है जो किसी देश के जन्म दर व मृत्यु दर के अलावा कई मानकों स्तरों पर गणना करते है।

उपादेयता :- कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण मे

- स्वास्थ्य संबंधी मानकों एवं सुधारवादी कदम उठाने मे आंकड़ों की महत्ता
- लक्षित कार्यक्रम की दिशा में सहायक।
- वर्ग विशेष की स्पष्ट स्थिति से भविष्य में योजना मे भी स्पष्टता नजर आएगी
- वैश्विक स्तर पर सकारात्मक आंकड़े देश की छवि को बेहतर करते है।

(3)

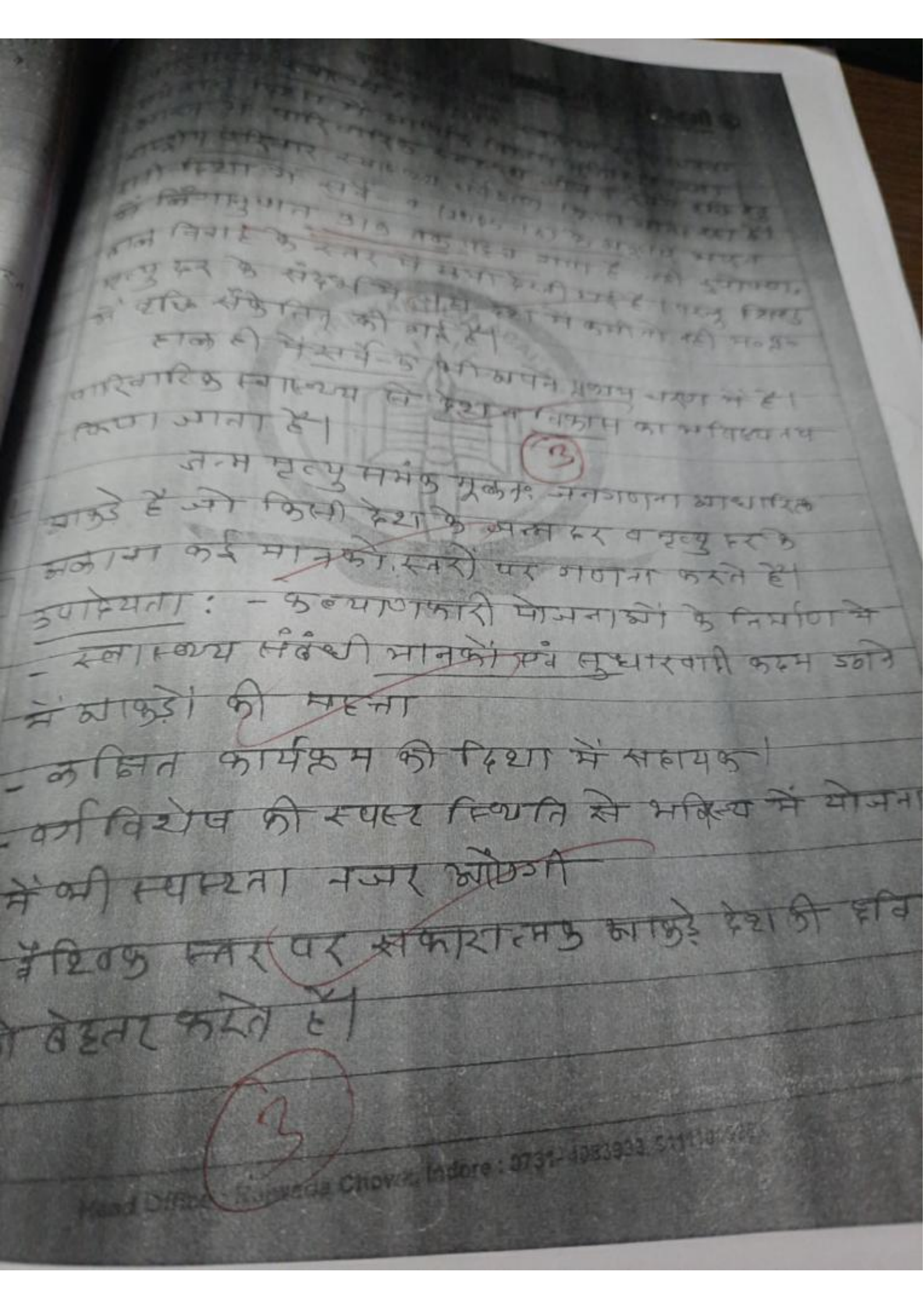

[illegible]

भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1.5 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करता है जो विकसित दे... की तुलना में काफी कम है। अतः स्वास्थ्य सुवि... सुधार की दिशा में प्रमुख प्रयास निम्नलिखि... है:

1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: नई नीति के तहत चिकित्सकीय प्राधिकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा आदि प्रावधानों को शामिल कि... गया है वहीं कुछ प्रमुख लक्ष्य है -

- जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च
- प्रजनन दर 2.1 के स्तर पर लाना
- कुपोषण में कमी। 90:90:90 के लक्ष्य शामिल करना। आदि।

2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - इसके ... राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य मि... अन्तर्गत सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे...

[illegible]

[illegible] की प्राथमिकताओं [illegible]

[illegible]

3) आयुष्मान भारत योजना – 2018 में शुरू 10 करोड़ परिवार के लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया गया है।

4) प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना – 2017 में शुरू संस्थागत प्रसव पर माता को 6000 रु की एकमुश्त राशि तीन चरणों के तहत प्रदान की जाती।

5) जननी सुरक्षा योजना – 2005 में शुरू केन्द्रीय प्रायोजित योजना जिसका लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके तहत संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करने पर गर्भवती महिला व कार्यकर्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6) जननी शिशु सुरक्षा योजना –

3

[illegible]

इस हेतु कई नीतियां व कार्यक्रम संचालित है-

1) स्किल इंडिया कार्यक्रम - 2015 में शुरू

इसके तहत 2022 तक भारत की 40 करोड़ जनसंख्या को कौशल विकास से युक्त करना है इस हेतु समय-समय पर कई कार्यक्रम व परियोजनाएं संचालित की जाएगी।

2) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - 2015 में

देश के अकुशल श्रम बल को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल युक्त करना ताकि वे देश का सही तरीके से आर्थिक विकास सुनिश्चित कर

3) मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना - इसके तहत 18 से 35 वर्ष को प्रशिक्षण दिया जायेगी।

4) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना - 2017 में

मध्यप्रदेश सरकार की यो

जिसके तहत हुनरवी नाम व्यक्ति को उचि

में प्रशिक्षित किया जायेगा।

[illegible]

... मानव संसाधन [illegible] ...

उपलब्ध करने से [illegible] ... राष्ट्र देश के प्राकृतिक संसाधन [illegible] उपयोगी प्रयोग की समस्या से [illegible] विनिर्माण, उत्पादन के स्तर पर नवीनता एवं अन्य देशों की तुलना में अधिक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।

निष्कर्षतः मानव संसाधन विकास की महत्ता से ही केन्द्रीय स्तर पर एक मंत्रालय का गठन किया गया है जो देश में मानव पूंजी को संसाधन बनाने का शीर्ष मंत्रालय है

5

7

[illegible]

[illegible] वर्तमान में [illegible] शिक्षा आदि [illegible]

[illegible] ऑनलाइन शिक्षा संबंधी सूचना

[illegible] है जिसका

विकसित हो [illegible] है [illegible]

प्रौद्योगिकी से ही [illegible]

शिक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के दौर में सभी

1) वर्तमान कोविड (महामारी) स्कूलों में कक्षा [illegible]

शासकीय एवं प्राइवेट (निजी) के माध्यम से [illegible]

आयोजन ऑनलाइन [illegible] के

हो रहा है।

2) स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति [illegible]

करने हेतु एम-शाला मित्र एप के माध्यम से

डिजिटल उपस्थिति की जा रही है।

3) डिजिटल बोर्ड जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से

विषयवार अध्ययन-अध्यापन कार्य किया [illegible]

रहा है।

4) स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखने

भी सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व है।

इन तमाम बिन्दुओं के

उपयोगिता समझी जा सकती है परन्तु

व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो [illegible]

[illegible]

1) [illegible] की कमी।

1) अध्यापकों की प्राथमिकता का विषय [illegible] भारत में असमानता है।

2) मूल्यांकन के स्तर पर एक मानक नियमों का पालन न होना।

3) निजी स्कूलों की फीस मनमानी सीमा एवं शासकीय स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति दर में गिरावट।

4) शाला छोड़ने की दर में गिरावट।

5) केवल शैक्षिक व्यवस्था होना। व्यवसायिक शिक्षा के प्रति उदासीनता।

6) शिक्षा के स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एवं प्रभाव देखा जाना।

7) स्कूल अवसंरचनात्मक कमी जिसमे- भवन, शौचालय, कमरे के स्तर पर अनियमितता आदि।

निष्कर्षतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 [illegible] तमाम कमियों को काफी स्तर तक दूर करने [illegible] दिशा में कारगर नजर आती है इसी के साथ [illegible] नात्मक एवं सरकारी स्तर पर भी प्रयास किये [illegible] चाहिए।